[Shri H. R. Bhardwaj]

and that is why this Bhagwati Committee came into existence and now we have concretised it in the shape of a Bill. Now wherever there is cooperation, it will be welcome.

I want to say a few things with regard to Constitution. We have not eroded any provincial autonomy. We have given full autonomy to the States to constitute their Legal Aid Boards, completely independent. Even now States are having these. You have the best network of legal aid in Tamilnadu. We like that and many people follow the example of Tamilnadu. Rajasthan has one of the best mechanisms; so has Madhya Pradesh. All these are successful. The full figures that I have with me, I have quoted. Now I do not understand why such a measure which is wholly necessary should be criticised. I think there is no room for criticism; there is room for improvement of the system, and that is where we need the cooperation of everybody.

Sir, once again I thank you all for giving me your cooperation.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: Just one clarification about composition. It is entirely different from the composition of the legal authority recommended by Bhagwati Committee.

SHRI H. R. BHARDWAJ: We have not accepted that recommendation.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: You have not included...

SHRI H. R. BHARDWAJ: We will give representation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The question is:

"That the Bill to constitute legal services authorities to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities, and to organise Lok Adalats to secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 30 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, I move.

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

Discontentment among Workers in Cement Industry

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): We will now take up Special Mentions. Shri Sukomal Sen. Absent.

SHRI DIPEN GHOSH (WEST BENGAL): Sir, what about the statement that Shri Bhagat promised at 5 o'clock?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): A few minutes afterwards. We may take up Special Mentions now. A few minutes afterwards from now.

श्री गुलाम रसूल मट्टू : (जम्मू और कश्मीर) महोदय, हिन्दी में कहावत है, "सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए" तो उसे भूला हुआ नहीं कहते।

श्री नरेश सी० पुगलिया (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सीमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले कामगारों की बात कहना चाहूंगा। इसके पहले भी स्पेशल मेंसन के माध्यम से यह बात उठायी गयी थी लेकिन आज चार महीने हो चुके है और इस समस्या को हमारे लेबर डिपार्टमेंट ने जिस ढंग से लेना चाहिए था नहीं लिया है। मैं कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में 1980 के बाद से सीमेंट का **प्रोडक्शन**

काफी तेजी से बढ़ा है और श्रीमत इंदिरा गांधी ने स्वयं देश में सीमेंट की कमी को देखते हुए कई बड़े-बड़े कारखाने लगाए जिससे कि उसमें भारी मात्रा में कामगार काम कर रहे हैं। लेकिन आज उनको उचित मजदूरी नहीं मिल रही है: उनके लिए जो सीमेंट वेज बोर्ड बनाया गया है, उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। हमारे यहां के बड़े उद्योगपति हैं, खासतौर पर चंद्रपुर जिले में जो मानीटर सीमेंट कारखाना है जोकि बिड़ला ग्रुप का एक कारखाना है, है, उस कारखाने में, जिसकी 110 करोड़ की लागत है, पिछले चार महीने से स्ट्राइक चल रही हैं और हंड्रेड परसेंट कामगार हड़ताल पर हैं। उसका कहना है कि सीमेंट वेज बोर्ड का इम्प्लीमेंटेशन किया जाये वह न करते हुए उस उद्योगपति ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में कर हड़ताल खत्म करने की कोशिश की है। इस प्रकार वहां अन्याय और अत्याचार हो रहा है। मजदूरों को जेल में बंद किया जा रहा है। गर्वनमेंट के साथ उनकी कंसल्टेशन

5 P.M. फेल्योर हुई है और फेल्योर की रिपोर्ट लेबर डिपार्टमेंट को देने के बाद भी हमारे लेबर कमिश्नर ने तथा दूसरे अधिकारियों ने जिस ढंग से उस पर निर्णय देना चाहिए था, नहीं लिया। आज भी मसला पेंडिंग है। लेबर मिनिस्टर ने हमें एक पत्र दिया है पिछले स्पेशल मेंशन की रिपोर्ट देते हुए कि वह उद्योगपति सीमेंट वेज बोर्ड लागू करना चाहता है। लेकिन स्ट्राइक खत्म होने के बाद तो मैं कहना चाहूंगा कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और उद्योगपति ऐलाउंस नहीं करते कि वे सीमेंट वेज बोर्ड को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तब तक कामगार स्ट्राइक वापस नहीं लेगें। (समय की घंटी)

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 25 एम०पीज ने इस पर एक कलिंग अटेंशन दिया था, वह मंजूर नहीं हुआ, तो आप इसमें मुझे दो मिनट का समय ज्यादा दीजिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन्होंने 15 दिसंबर, 1985 को फैक्ट्री चालू की और 1985 में डेप्रिशियेशन ऐलाउंस का 10 करोड़ रुपया 85 लाख रुपया और इंवेस्टमेंट का ऐलाउंस का 15 करोड़ 8 लाख रुपया तथा 1986 का डेप्रिशियेशन ऐलाउंस का 12.26 करोड़ रुपया और इंवेस्ट ऐलाउंस का 4.33 करोड़ रुपया इनकम टैक्स में रिबेट लिया है। एक तरफ सरकार से वे सुविधा लेते हैं तो कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री चालू है और दूसरी तरफ जब कामगार को पैसा देने का सवाल आता है तो कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बंद है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि लेबर मिनिस्टर इसकी ओर ध्यान दें और इस मामले को तुरन्त सुलझाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): मैं इसका समर्थन करता हूं जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है।

REPORTED SLANDER AGAINST THE PRIME MINISTER

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I wiuld like to draw the attention of this august House to a very serious problem, serious slander of the honourable Prime Minister, Rajiv Gandhi, comparing his acts with those of film stars, having the effect of lowering him in the eyes of the public. This has appeared in a daily newspaper, *The Afternoon*, of Saturday, the 29th August 1987. I quote :

> *"Rajiv Amitabh will soon fade away*
>
> Mr. Rajiv Gandhi and Amitabh Bachchal are like sex appeal stars in politics. Sex appeal film stars will shine for a short period and then fade away. Similarly, Rajiv Gandhi and Bachchan will fade away from Indian Politics very soon due to their misdeeds."

Sir, this is slander.

Sir, though I believe in the freedom of the press, my faith is equal in the national symbols and their dignity also. The Prime Minister, in a democracy, is a pivot of people's faith. Such slander seriously affects the democratic faith of the people and, as such, it is condemnable. I would be happy if the Home Ministry looks into this type of slander and evolves methods to curb it. The matter